

महिला उद्यमियों पर सांस्कृतिक एवं पारंपरिक परिस्थितियों का प्रतिकूल प्रभाव : मध्य प्रदेश के धार जिले के संदर्भ में

पीएच.डी. शोधार्थी :- खुशबू पाटीदार

शोध पर्यवेक्षक :- डॉ. सपना राठौर

प्रबंधन एवं वाणिज्य संकाय

यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जयपुर (राजस्थान)

सारांश

प्रस्तुत अध्ययन का विषय "महिला उद्यमियों पर सांस्कृतिक एवं पारंपरिक परिस्थितियों का प्रतिकूल प्रभाव : मध्य प्रदेश के धार जिले के संदर्भ में" है। इस अध्ययन के अंतर्गत धार जिले के पाँच ग्रामीण क्षेत्रों का चयन किया गया तथा वहाँ निवासरत महिला उद्यमियों एवं महिलाओं की सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का अध्ययन किया गया।

अध्ययन से ज्ञात हुआ कि आज भी अनेक ग्रामीण महिलाएँ रूढ़िवादी परंपराओं, घूँघट प्रथा, सीमित शैक्षिक अवसरों, आर्थिक अभाव, बाल विवाह, आवागमन पर प्रतिबंध तथा रोजगार एवं व्यवसाय संबंधी बाधाओं का सामना कर रही हैं। इन परिस्थितियों का महिलाओं के व्यक्तित्व विकास, आत्मनिर्भरता तथा उद्यमिता विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

अध्ययन में यह भी पाया गया कि अधिकांश महिलाओं को परिवार एवं समाज से अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहीं हो पाता, जिसके कारण वे अपनी क्षमता, रुचि तथा कौशल का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाती हैं। कई मामलों में महिलाओं की शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता तथा कम आयु में विवाह कर दिया जाता है, जिससे उनके आर्थिक एवं सामाजिक विकास की संभावनाएँ सीमित हो जाती हैं।

यद्यपि वर्तमान समय में कुछ महिलाएँ स्वरोजगार एवं छोटे व्यवसायों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रही हैं, फिर भी पारंपरिक मान्यताएँ एवं सामाजिक प्रतिबंध उनके विकास में बाधक बने हुए हैं। अध्ययन यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि महिलाओं को शिक्षा, आर्थिक संसाधन, प्रशिक्षण तथा सामाजिक समर्थन उपलब्ध कराकर उन्हें उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। इससे न केवल महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी।

मुख्य शब्द

महिला उद्यमिता, सांस्कृतिक प्रभाव, पारंपरिक मान्यताएँ, घूँघट प्रथा, ग्रामीण महिलाएँ, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा का अभाव, आर्थिक बाधाएँ, बाल विवाह, सामाजिक प्रतिबंध, उद्यमिता विकास, धार जिला।

परिचय

भारत के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। देश की कुल जनसंख्या का लगभग आधा भाग महिलाओं का है तथा बड़ी संख्या में महिलाएँ कृषि क्षेत्र में कृषक एवं कृषि श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं। समय के साथ महिला साक्षरता और कार्य सहभागिता में वृद्धि देखने को मिली है, जिससे उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। वर्तमान समय में महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता तथा सामाजिक न्याय जैसे विषय विकास की प्रमुख अवधारणाओं के रूप में उभरकर सामने आए हैं। महिला सशक्तिकरण एक सतत प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से महिलाएँ जागरूकता, आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता तथा अपने जीवन से जुड़े संसाधनों और अवसरों पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करती हैं।

समावेशी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों को प्राथमिकता वाले राज्यों के रूप में चिन्हित किया है। स्वयं सहायता समूह (Self-Help Groups - SHGs) महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान का एक प्रभावी माध्यम बनकर उभरे हैं। इन समूहों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़कर महिलाओं को बचत एवं ऋण सुविधाओं तक पहुँच उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2012 में प्रारंभ की गई राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर उनकी आजीविका एवं आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करना है। मध्य प्रदेश में इस मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अनेक जिलों के विभिन्न विकासखंडों का चयन किया गया है।

भारत की ग्रामीण संस्कृति विविध परंपराओं, रीति-रिवाजों एवं सामाजिक मान्यताओं से समृद्ध है। प्रत्येक समुदाय की अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान तथा जीवनशैली होती है। इन परंपराओं का समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, किन्तु कुछ परिस्थितियों में यही परंपराएँ महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में बाधा भी उत्पन्न करती हैं।

मध्य प्रदेश के धार जिले के अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी महिलाएँ पारंपरिक मान्यताओं एवं सामाजिक प्रतिबंधों के अंतर्गत जीवन व्यतीत करती हैं। घूँघट प्रथा, महिलाओं की शिक्षा के प्रति उदासीनता, कम आयु में विवाह, रोजगार एवं व्यवसाय के अवसरों की कमी तथा स्वतंत्र निर्णय लेने की सीमित क्षमता जैसी समस्याएँ महिलाओं की प्रगति को प्रभावित करती हैं।

महिला उद्यमिता वर्तमान समय में आर्थिक विकास एवं महिला सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुकी है। किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक महिला उद्यमियों को सांस्कृतिक एवं पारंपरिक कारणों से अपने व्यवसाय के संचालन एवं विस्तार में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई महिलाएँ अपने व्यवसाय को केवल सीमित दायरे तक ही संचालित कर पाती हैं क्योंकि उन्हें सामाजिक अपेक्षाओं, पारिवारिक दबावों तथा रूढ़िवादी सोच का सामना करना पड़ता है।

प्रस्तुत अध्ययन में धार जिले के पाँच ग्रामों का चयन कर यह जानने का प्रयास किया गया है कि सांस्कृतिक एवं पारंपरिक परिस्थितियाँ महिला उद्यमियों के व्यवसाय, निर्णय क्षमता, आर्थिक स्वतंत्रता तथा सामाजिक स्थिति को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। साथ ही, महिलाओं के समक्ष उपस्थित प्रमुख समस्याओं एवं उनके संभावित समाधान पर भी विचार किया गया है।

यह अध्ययन महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास तथा उद्यमिता के क्षेत्र में उपयोगी जानकारी प्रदान करता है तथा महिलाओं के लिए अधिक अनुकूल सामाजिक एवं आर्थिक वातावरण निर्माण की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

उद्देश्य

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के सशक्तिकरण के स्तर का मूल्यांकन करना है।

साहित्य समीक्षा

धनोतिया (2012) ने प्रतिवेदित किया कि स्व-सहायता समूहों (Self Help Groups) में शामिल अधिकांश महिलाएँ निम्न ऋण-लेनदेन श्रेणी से संबंधित थीं, जिनका प्रतिशत **41.83 प्रतिशत** था।

थंगमणि एवं मुथुसेल्वी (2013) ने कोयंबटूर जिले की मेट्रूपालयम तहसील में महिलाओं के सशक्तिकरण पर स्व-सहायता समूहों की भूमिका का अध्ययन किया। अध्ययन से ज्ञात हुआ कि अधिकांश उत्तरदाताओं की मासिक आय **₹5000 से कम** थी।

दास (2013) ने महिलाओं के सशक्तिकरण में स्व-सहायता समूहों की भूमिका पर बरगढ़ क्षेत्र में अध्ययन किया। अध्ययन के अनुसार अधिकांश महिला उत्तरदाता (**57.33 प्रतिशत**) मध्यम आय वर्ग से संबंधित थीं, जबकि **29.34 प्रतिशत** निम्न आय वर्ग तथा **13.33 प्रतिशत** उच्च आय वर्ग से संबंधित थीं।

सिंह (2017) ने हिमाचल प्रदेश के द्रंग विकासखंड में अध्ययन किया और पाया कि स्व-सहायता समूहों में महिलाओं की सहभागिता ने उनके **सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण** पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव डाला।

अनुसंधान पद्धति

वर्तमान में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.) कार्यक्रम धार जिले के सभी 13 विकासखण्डों में संचालित किया जा रहा है। अध्ययन हेतु धार एवं तिरला विकासखण्डों का चयन किया गया, क्योंकि इन क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लाभान्वित ग्रामीण महिलाओं की संख्या अपेक्षाकृत अधिक थी।

अध्ययन में उत्तरदाताओं के चयन के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से लाभान्वित महिलाओं की सूची प्राप्त की गई। इस सूची में से स्व-सहायता समूहों (Self Help Groups) की कुल 120 महिला सदस्यों का चयन यादृच्छिक निदर्शन (Random Sampling) पद्धति के आधार पर किया गया, जिससे अध्ययन में निष्पक्षता एवं प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके।

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य स्व-सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करना, उनमें उद्यमिता के स्तर का मूल्यांकन करना तथा उनके सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रभाव का अध्ययन करना था।

अध्ययन प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आँकड़ों पर आधारित है। प्राथमिक आँकड़ों का संकलन प्रश्नावली एवं साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से किया गया, जबकि द्वितीयक आँकड़े विभिन्न पुस्तकों, शोध-पत्रों, शोध-प्रबंधों, सरकारी प्रतिवेदनों, पत्र-पत्रिकाओं तथा अन्य प्रकाशित स्रोतों से प्राप्त किए गए।

परिणाम :

तालिका : स्व-सहायता समूह (SHG) सदस्यों का मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण स्तर (n = 120)

(A) मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण (Psychological Empowerment)

क्र.सं.	पहलू	उच्च	मध्यम	निम्न	कुल स्कोर	औसत स्कोर
1	आत्मविश्वास	58	37	25	273	2.27
2	साहस	41	40	29	232	1.93
3	आत्मनिर्भरता	55	32	33	262	2.18
4	कैरियर महत्वाकांक्षा	48	34	38	250	2.08
5	आत्म-छवि	39	53	28	251	2.09
	औसत					2.11

(B) सांस्कृतिक सशक्तिकरण (Cultural Empowerment)

क्र.सं.	पहलू	उच्च	मध्यम	निम्न	कुल स्कोर	औसत स्कोर
1	परिवार के बाहर पुरुषों से संवाद की स्वतंत्रता	57	37	26	271	2.25
2	त्योहार एवं धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने की स्वतंत्रता	68	35	17	291	2.42
3	इच्छानुसार वस्त्र पहनने की स्वतंत्रता	51	41	28	263	2.19

क्र.सं.	पहलू	उच्च	मध्यम	निम्न	कुल स्कोर	औसत स्कोर
4	सार्वजनिक स्थान/कार्यालय में जाने की स्वतंत्रता	48	40	32	256	2.13
5	भोजन संबंधी निर्णय लेने की स्वतंत्रता	45	38	37	247	2.06
6	विवाह समारोह में भाग लेने की स्वतंत्रता	41	40	39	242	2.01
	औसत					2.17

(C) सामाजिक सशक्तिकरण (Social Empowerment)

क्र.सं.	पहलू	उच्च	मध्यम	निम्न	कुल स्कोर	औसत स्कोर
1	स्व-शिक्षा	64	31	25	279	2.32
2	परिवार के बाहर कार्य करने की स्वतंत्रता	58	34	28	270	2.25
3	परिवार नियोजन संबंधी निर्णयों में भागीदारी	48	60	12	276	2.30
4	सामुदायिक गतिविधियों में सहभागिता	60	24	36	264	2.20
5	सामाजिक सुरक्षा की भावना	62	38	20	282	2.35
6	बच्चों की शिक्षा संबंधी निर्णयों में भागीदारी	73	31	16	297	2.47
7	आधुनिक तकनीक तक पहुँच	50	35	35	255	2.12
	औसत					2.28

(D) आर्थिक सशक्तिकरण (Economic Empowerment)

क्र.सं.	पहलू	उच्च	मध्यम	निम्न	कुल स्कोर	औसत स्कोर
1	रोजगार/व्यवसाय के चयन की स्वतंत्रता	62	41	17	285	2.37
2	बैंक में व्यक्तिगत खाते का संचालन	48	41	31	257	2.14
3	घर/उद्यम में आधुनिक तकनीक अपनाने संबंधी निर्णयों में सहभागिता	41	39	40	241	2.00
4	उत्पादों के विपणन संबंधी निर्णयों में सहभागिता	57	49	14	283	2.35
5	श्रमिकों की नियुक्ति का अधिकार	55	36	29	266	2.21
	औसत					2.21

(E) राजनीतिक सशक्तिकरण (Political Empowerment)

क्र.सं.	पहलू	उच्च	मध्यम	निम्न	कुल स्कोर	औसत स्कोर
1	वर्तमान में राजनीतिक पद धारण करना	46	40	34	252	2.10
2	सक्रिय राजनीति में भाग लेने की स्वतंत्रता	48	41	31	257	2.14
3	मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता	51	39	30	261	2.17
4	महिलाओं से संबंधित कानूनों की जानकारी	45	42	33	252	2.10
5	राजनीतिक संस्थाओं के प्रति जागरूकता	39	57	24	255	2.12
	औसत					2.12

स्रोत: स्व-सहायता समूह (SHG) की 120 महिला सदस्यों पर आधारित अध्ययन।

स्व-सहायता समूह (SHG) सदस्यों का सशक्तिकरण

(क) मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण (Psychological Empowerment)

मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण के संदर्भ में यह पाया गया कि महिला सशक्तिकरण सूचकांक आत्मविश्वास (2.27) में सर्वाधिक था। इसके पश्चात आत्मनिर्भरता (2.18), आत्म-छवि (2.09), साहस (2.08) तथा करियर महत्वाकांक्षा (1.93) का स्थान रहा। इससे स्पष्ट होता है कि स्व-सहायता समूहों में सहभागिता से महिलाओं में आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता की भावना विकसित हुई है, जिससे वे अपने जीवन एवं व्यवसाय संबंधी निर्णय लेने में अधिक सक्षम बनी हैं।

(ख) सांस्कृतिक सशक्तिकरण (Cultural Empowerment)

सांस्कृतिक सशक्तिकरण के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण सूचकांक त्योहारों एवं धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने की स्वतंत्रता (2.42) में सर्वाधिक पाया गया। इसके बाद परिवार के बाहर पुरुषों से संवाद करने की स्वतंत्रता (2.25), अपनी पसंद के वस्त्र पहनने की स्वतंत्रता (2.19), धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलों पर जाने की स्वतंत्रता (2.13), भोजन संबंधी निर्णय लेने की स्वतंत्रता (2.06) तथा विवाह समारोहों में भाग लेने की स्वतंत्रता (2.01) का स्थान रहा। यह दर्शाता है कि महिलाओं को सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता प्राप्त हो रही है।

(ग) सामाजिक सशक्तिकरण (Social Empowerment)

सामाजिक सशक्तिकरण के अंतर्गत बच्चों की शिक्षा संबंधी निर्णयों में सहभागिता (2.47) का स्तर सर्वाधिक पाया गया। इसके पश्चात सामाजिक सुरक्षा की भावना (2.35), स्व-शिक्षा (2.32), परिवार नियोजन संबंधी निर्णयों में सहभागिता (2.30), परिवार के बाहर कार्य करने की स्वतंत्रता (2.25), सामुदायिक गतिविधियों में सहभागिता (2.20) तथा आधुनिक तकनीक तक पहुँच (2.12) का स्थान रहा। यह परिणाम महिलाओं की सामाजिक निर्णय प्रक्रिया में बढ़ती भागीदारी एवं जागरूकता को दर्शाता है।

(घ) आर्थिक सशक्तिकरण (Economic Empowerment)

आर्थिक सशक्तिकरण के अंतर्गत रोजगार अथवा कार्य के चयन की स्वतंत्रता (2.37) सर्वाधिक पाई गई। इसके पश्चात उत्पादों के विपणन संबंधी निर्णयों में सहभागिता (2.35), श्रमिकों की नियुक्ति का अधिकार (2.21), बैंक में व्यक्तिगत खाते का संचालन (2.14) तथा घर एवं उद्यम में आधुनिक तकनीक अपनाने संबंधी निर्णयों में सहभागिता (2.00) का स्थान रहा। इससे स्पष्ट होता है कि महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों एवं निर्णयों में भूमिका निरंतर सुदृढ़ हो रही है।

(ङ) राजनीतिक सशक्तिकरण (Political Empowerment)

राजनीतिक सशक्तिकरण के संदर्भ में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता (2.17) का स्तर सर्वाधिक पाया गया। इसके पश्चात सक्रिय राजनीति में भागीदारी की स्वतंत्रता (2.14),

राजनीतिक संस्थाओं के प्रति जागरूकता (2.12), महिलाओं से संबंधित कानूनों की जानकारी (2.10) तथा वर्तमान में राजनीतिक पद धारण करना (2.10) का स्थान रहा। यह इंगित करता है कि महिलाओं में राजनीतिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ रही है।

निष्कर्ष (Conclusion)

अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित प्रमुख निष्कर्ष प्राप्त हुए—

- महिला सशक्तिकरण सूचकांक मनोवैज्ञानिक पक्ष में **आत्मविश्वास** के क्षेत्र में सर्वाधिक पाया गया।
- सांस्कृतिक सशक्तिकरण के अंतर्गत **त्योहारों एवं धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने की स्वतंत्रता** का स्तर सर्वाधिक रहा।
- सामाजिक सशक्तिकरण में **बच्चों की शिक्षा संबंधी निर्णयों में सहभागिता** सबसे अधिक पाई गई।
- आर्थिक सशक्तिकरण के अंतर्गत **रोजगार चयन की स्वतंत्रता एवं विपणन संबंधी निर्णयों में सहभागिता** का स्तर अपेक्षाकृत अधिक पाया गया।
- राजनीतिक सशक्तिकरण में **मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता** सर्वाधिक रही।
- स्व-सहायता समूहों की सदस्यता ने महिलाओं के आत्मविश्वास, सामाजिक सहभागिता, आर्थिक स्वतंत्रता एवं राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि स्व-सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण का एक प्रभावी माध्यम हैं।

संदर्भ (References)

धनोटिया, बरखा (2012), स्व-सहायता समूहों के माध्यम से महिला उद्यमशील व्यवहार का अध्ययन, एम.एससी. (कृषि) शोधप्रबंध, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

डैश, एम.के. (2013), महिला सशक्तिकरण में स्व-सहायता समूहों की भूमिका: बरगढ़ का अध्ययन, ओडिशा रिव्यू, संबलपुर विश्वविद्यालय, ज्योतिविहार, बुरला, संबलपुर, पृ. 70-74।

सिंह, एस.पी., चौहान, के.एस. एवं रघुवंशी, एस. (2014), सब्जी उत्पादन में कृषि महिलाओं की निर्णय-निर्माण में सहभागिता, एग्रीकल्चर जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी एडवांस्ड रिसर्च, 3(2): 19-25।

सिंह, यू. (2017), स्व-सहायता समूह एवं महिला सशक्तिकरण: हिमाचल प्रदेश के द्रंग ब्लॉक का मूल्यांकन, मैनेजमेंट इनसाइट, 13(1): 45-53।

थंगमणि, एस. एवं मुथुसेल्वी, एस. (2013), स्व-सहायता समूहों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का अध्ययन: कोयम्बटूर जिले के मेट्टूपालयम तालुक के विशेष संदर्भ में, IOSR जर्नल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट, 8(6): 17-24।